

भारत में सामाजिक सुरक्षा की स्थिति

प्रलिस के लयः

वशिव सामाजिक सुरक्षा रपिरट 2020-22: एशया और प्रशांत के लयः कषेत्रीय सहयोग रपिरट), अंतरराष्टरीय श्रम संगठन (ILO), महात्मा गांधी राष्टरीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम (MGNREGA) ।

मेन्स के लयः

भारत में सामाजिक सुरक्षा ।

चर्चा में क्यों?

अंतरराष्टरीय श्रम संगठन (ILO) द्वारा सामाजिक सुरक्षा पर नवीनतम रपिरट (वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रपिरट 2020-22: एशया और प्रशांत के लयः कषेत्रीय सहयोग रपिरट) के अनुसार, बांग्लादेश के 28.4% स्तर से भी कम केवल 24.4% भारतीयों को कसी भी प्रकार के सामाजिक संरक्षण लाभ मलता है ।

सामाजिक सुरक्षा:

- सामाजिक सुरक्षा प्रणालयाँ वयक्तियों और परिवारों, वशेष रूप से गरीब तथा कमजोर लोगों, संकटों व समस्याओं का सामना करने, नौकरी खोजने, उत्पादकता में सुधार करने, अपने बच्चों के स्वास्थय एवं शकषिा में नवश करने तथा बढ़ती उमर की आबादी की रक्षा करने में मदद करती हैं ।

रपिरट के मुख्य बडुः

- परचयः** रपिरट ILO की 'वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रपिरट 2021-22' की सहयोगी है, जो एशया और प्रशांत कषेत्र में सामाजिक सुरक्षा का एक कषेत्रीय अवलोकन प्रदान करती है ।
- वैश्वकः**
 - सामाजिक सुरक्षा:** यह बताती है क मंगोलया, न्यूजीलैंड, सगिापुर और ऑस्ट्रेलया में 100% सामाजिक सुरक्षा नेटवर्क है, जबक म्याँमार और कंबोडया में यह 10% से भी कम है ।
 - कम कवरेज:** रपिरट के अनुसार एशया प्रशांत कषेत्र में चार श्रमकों में से तीन काम के दौरान बीमारी या चोट लगने की स्थतः में सुरक्षतः नहीं हैं ।
 - प्रतः वयक्तः कम **सकल घरेलू उत्पाद (GDP)** वाले देशों में कार्य कषतः कवरेज नमः स्तर का होता है, उदाहरण के लयः अफगानस्तान, भारत, नेपाल और पाकस्तान अपने श्रमकों के **5% से कम कार्य कषतः कवरेज कवर** करते हैं ।
 - असमान कवरेज:** रपिरट के अनुसार वर्ष 2020 तक वैश्वक आबादी का केवल **9% कम से कम एक सामाजिक सुरक्षा लाभ** से प्रभावी रूप से कवर कया गया था, जबक **शेष 53.1% 4.1 बलियन लोगों को पूरी तरह से असुरक्षतः छोड़ दया गया था** ।
 - असमान कवरेज:** रपिरट के अनुसार, 2020 तक, वैश्वक आबादी का केवल 46.9% प्रभावी रूप से कम से कम एक सामाजिक सुरक्षा लाभ द्वारा कवर कया गया था, जबक **शेष 53.1% 1 बलियन लोगों को पूरी तरह से असुरक्षतः छोड़ दया गया था** ।
 - रपिरट में आगे कहा गया है क दुनया में कामकाजी उमर की आबादी का बड़ा हससा **4% या 4 बलियन लोग** केवल आंशक रूप से संरक्षतः हैं या बलकुल भी सुरक्षतः नहीं हैं ।
 - लैंगक असमानता:** सामाजिक सुरक्षा कवरेज में अंतरनहः लैंगक असमानता को उजागर करते हुए, रपिरट में महिलाओं के कवरेज में पुरुषों के मुकाबले **8% अकों की कमी** दर्ज की गई है ।
- भारतीय परपरेक्षयः**
 - सामाजिक सुरक्षा में कम नवश:** रपिरट में कहा गया है क सामाजिक सुरक्षा में अपेक्षाकृत कम नवश के कारण, यानी भारतीय आबादी का केवल **4%, गैर-अंशदायी लाभों के तहत हस्तांतरतः राशा** आमतौर पर परयाप्त सुरक्षा प्रदान करने के लयः बहुत कम है ।
 - कवरेज में असमानता:** अंशदायी योजनाओं के साथ आम तौर पर औपचारक कषेत्र में काम करने वालों और गैर-अंशदायी योजनाओं तक सीमतः होने के कारण, भारत के सामाजिक सुरक्षा लाभ **प्रतः वयक्तः सकल घरेलू उत्पाद के 5% से कम** हैं ।

- हाल की पहल: इसने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम (Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Programme-MGNREGA) जैसे सामाजिक सुरक्षा के विभिन्न स्तरों के अपने प्रगतशील विस्तार से अंशदायी और गैर-अंशदायी योजनाओं के संयोजन के माध्यम से प्राप्त भारत की उच्च कवरेज दर की सराहना की, जो अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों के लिये 100 दिनों तक कार्य सुरक्षा की गारंटी प्रदान करता है।

सामाजिक सुरक्षा के संबंध में भारत सरकार की विभिन्न पहलें:

- प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना (Pradhan Mantri Shram Yogi Maan-Dhan Yojana (PM-SYM))
- राष्ट्रीय पेंशन योजना (National Pension Scheme-NPS)
- प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना (Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Yojana-PMJJBY)
- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana-PMSBY)
- अटल पेंशन योजना
- राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास नगिम (National Safai Karamcharis Finance and Development Corporation-NSKDFC)
- हाथ से मेला उताने वालों के पुनर्वास हेतु स्वरोजगार योजना

अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन International Labour Organisation (ILO):

- यह संयुक्त राष्ट्र की एकमात्र त्रिपक्षीय संस्था है। यह श्रम मानक निर्धारित करने, नीतियों को विकसित करने एवं सभी महिलाओं तथा पुरुषों के लिये सभ्य कार्य को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रम तैयार करने हेतु 187 सदस्य देशों की सरकारों, नियोक्ताओं और श्रमिकों को एक साथ लाता है।
 - वर्ष 1969 में अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन को नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया।
- वर्ष 1919 में वर्साय की संधि द्वारा राष्ट्र संघ की एक संबद्ध एजेंसी के रूप में इसकी स्थापना हुई।
- वर्ष 1946 में यह संयुक्त राष्ट्र से संबद्ध पहली विशिष्ट एजेंसी बन गया।
- मुख्यालय: इसका मुख्यालय जनिवा, स्विट्ज़रलैंड में है।
- अन्य रिपोर्ट:
 - सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट
 - विश्व रोजगार और सामाजिक आउटलुक
 - विश्व रोजगार और सामाजिक दृष्टिकोण
 - विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट
 - वैश्विक वेतन रिपोर्ट

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्षों के प्रश्न:

प्रलिमिस:

प्रश्न . 'अटल पेंशन योजना' के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं? (2016)

1. यह मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर लक्षित एक न्यूनतम गारंटीकृत पेंशन योजना है।
2. एक परिवार का एक ही सदस्य इस योजना में शामिल हो सकता है। यह ग्राहक की मृत्यु के बाद जीवन भर के लिये पत्नी या पत्नी हेतु समान राशि की पेंशन गारंटी है।

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: C

व्याख्या:

- यह योजना मई 2015 में सभी भारतीयों, विशेष रूप से गरीबों, वंचितों और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिये एक सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई थी।
- APY असंगठित क्षेत्र के सभी नागरिकों पर केंद्रित है, जो पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (Pension Fund Regulatory and Development Authority-PFRDA) द्वारा प्रशासित राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) में शामिल हो गए हैं और जो किसी वैधानिक सामाजिक

सुरक्षा योजना के सदस्य नहीं हैं।

- APY 18-40 वर्ष के आयु वर्ग के असंगठित क्षेत्र के सभी नागरिकों पर केंद्रित है। APY के तहत, ग्राहकों को 60 वर्ष की आयु में उनके योगदान के आधार पर नश्चिती न्यूनतम पेंशन (₹1000-5000) प्राप्त होगी। **अतः कथन 1 सही है।**
- APY में शामिल होने वाले परिवार के सदस्यों की संख्या पर कोई रोक नहीं है। **अतः कथन 2 सही नहीं है।**
- अभिदाता की मृत्यु होने पर उसके पति/पत्नी को जीवन भर के लिये उतनी ही पेंशन दी जाएगी। **अतः कथन 3 सही है।**
- पति या पत्नी और ग्राहक दोनों की मृत्यु के बाद, नामांकित व्यक्ति पेंशन राशि प्राप्त करने का हकदार होगा।

मेनस:

प्र. क्या दवियांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 समाज में इच्छति लाभार्थियों के सशक्तकरण और समावेशन के लिये प्रभावी तंत्र सुनश्चिति करता है? चर्चा कीजिये। (2017)

स्रोत: बजिनेस स्टैंडर्ड

PDF Refernece URL: <https://www.drishtiiias.com/hindi/printpdf/status-of-social-protection-in-india>

